

# भारत में गिग इकोनॉमी का रोजगार सृजन पर प्रभाव: 2025-2030 के बीच अनुमानित 2.35 लाख करोड़ रुपये GDP योगदान का विश्लेषण

डॉ. दिलीप तिवारी

अतिथि विद्वान- वाणिज्य विभाग

शासकीय ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय, रीवा, मध्य प्रदेश

सारांश (Abstract)

गिग इकोनॉमी भारत में तेजी से उभरता हुआ क्षेत्र है, जो डिजिटल प्लेटफॉर्म (जैसे Ola, Uber, Swiggy, Zomato) के माध्यम से लचीले रोजगार प्रदान करता है। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार, FY 2021 में 77 लाख गिग वर्कर्स से बढ़कर FY 2025 में 1.2 करोड़ हो गए हैं, जो कुल कार्यबल का 2% से अधिक है। 2029-30 तक गैर-कृषि गिग कार्यबल 6.7% तक पहुँचने और ₹2.35 लाख करोड़ GDP योगदान देने का अनुमान है। यह शोध पत्र गिग इकोनॉमी के रोजगार सृजन, आर्थिक योगदान, चुनौतियों (आय अस्थिरता, सामाजिक सुरक्षा की कमी) और नीतिगत सुझावों का विश्लेषण करता है। द्वितीयक डेटा पर आधारित यह अध्ययन दर्शाता है कि गिग इकोनॉमी रोजगार सृजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है, लेकिन श्रमिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की आवश्यकता है।



कीवर्ड्स (Keywords): गिग इकोनॉमी, रोजगार सृजन, GDP योगदान, डिजिटल प्लेटफॉर्म, सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26, NITI Aayog, भारत में गिग वर्कर्स

### परिचय (Introduction)

भारत की अर्थव्यवस्था में डिजिटल परिवर्तन ने कार्य की प्रकृति को बदल दिया है। गिग इकोनॉमी, जिसमें कार्यकर्ता कार्य-आधारित (task-based) अनुबंध पर काम करते हैं, बिना स्थायी नौकरी के लचीलेपन प्रदान करती है। NITI Aayog की 2022 रिपोर्ट के अनुसार, 2020-21 में 77 लाख गिग वर्कर्स थे, जो 2029-30 तक 2.35 करोड़ (23.5 मिलियन) तक पहुँचने का अनुमान है।

आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 में उल्लेख है कि FY 2021 से FY 2025 तक गिग वर्कर्स की संख्या में 55% वृद्धि हुई, जो अब कुल कार्यबल का 2% से अधिक है। स्मार्टफोन प्रवेश (80 करोड़ से अधिक उपयोगकर्ता) और UPI लेनदेन (मासिक 15 अरब) ने इस वृद्धि को बढ़ावा दिया है। 2029-30 तक गैर-कृषि गिग कार्य 6.7% कार्यबल का हिस्सा बन सकता है और ₹2.35 लाख करोड़ GDP में योगदान दे सकता है। आधुनिक भारत की अर्थव्यवस्था में डिजिटल परिवर्तन ने कार्य की प्रकृति को मूल रूप से बदल दिया है। जहाँ पारंपरिक रोजगार स्थायी नौकरी, निश्चित वेतन, सामाजिक सुरक्षा और लाभों पर आधारित था, वहीं गिग इकोनॉमी ने लचीले, कार्य-आधारित (task-based) और प्लेटफॉर्म-मध्यस्थ रोजगार का एक नया मॉडल प्रस्तुत किया है। गिग इकोनॉमी में कार्यकर्ता डिजिटल प्लेटफॉर्म (जैसे Ola, Uber, Swiggy, Zomato, Urban Company, Upwork आदि) के माध्यम से डिलीवरी, राइड-शेयरिंग, फ्रीलांसिंग, क्विक कॉमर्स और अन्य सेवाओं में कार्य करते हैं, बिना स्थायी नियोक्ता, फिक्स्ड घंटों या पारंपरिक लाभों के। यह मॉडल युवाओं, ग्रामीण प्रवासियों और महिलाओं के लिए विशेष रूप से आकर्षक साबित हुआ है, क्योंकि इसमें समय और स्थान की स्वतंत्रता प्रदान की जाती है।

भारत में गिग इकोनॉमी की वृद्धि अभूतपूर्व रही है।



इस वृद्धि के प्रमुख कारक हैं: स्मार्टफोन प्रवेश: 80 करोड़ से अधिक उपयोगकर्ता। डिजिटल भुगतान का विस्तार: मासिक 15 अरब से अधिक UPI लेनदेन। प्लेटफॉर्म इकोसिस्टम का विस्तार: ई-कॉमर्स, लॉजिस्टिक्स, फूड डिलीवरी और अन्य सेवाओं में तेजी से स्केल-अप। COVID-19 के बाद की रिकवरी: जहां पारंपरिक नौकरियाँ प्रभावित हुईं, वहीं गिग इकोनॉमी ने त्वरित रोजगार अवसर प्रदान किए। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 में स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि गिग इकोनॉमी ने अनौपचारिक रोजगार को प्लेटफॉर्म-आधारित और इकोसिस्टम-एकीकृत भूमिकाओं में परिवर्तित किया है। यह क्षेत्र अब भारत की सेवा अर्थव्यवस्था का एक संरचनात्मक हिस्सा बन चुका है। अनुमान है कि 2029-30 तक यह क्षेत्र ₹2.35 लाख करोड़ का योगदान भारत की सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में देगा। यह योगदान मुख्य रूप से उत्पादकता वृद्धि, सेवा क्षेत्र विस्तार, कर संग्रह और अप्रत्यक्ष प्रभावों (जैसे उपभोक्ता खर्च बढ़ना) से आएगा। यह योगदान भारत की कुल GDP का लगभग 0.8-1.25% हो सकता है, जो 7%+ वार्षिक GDP वृद्धि दर के संदर्भ में महत्वपूर्ण है।

गिग इकोनॉमी के रोजगार सृजन पर प्रभाव बहुआयामी है। यह लाखों नौकरियाँ पैदा कर रही है, विशेषकर युवाओं (18-35 आयु वर्ग) के लिए, जो कुल गिग वर्कर्स का 60%+ हिस्सा हैं। ग्रामीण और टियर-2/3 शहरों से आने वाले प्रवासियों के लिए यह शहरी अवसरों का द्वार खोल रहा है। महिलाओं की भागीदारी भी बढ़ रही है, हालांकि अभी भी कम (कुल का 10% से कम)। यह मॉडल लचीलेपन (flexibility) प्रदान करता है, जिससे कार्यकर्ता अपनी आय को नियंत्रित कर सकते हैं और बहु-कार्य (multi-gigging) कर सकते हैं। यह शोध पत्र गिग इकोनॉमी के रोजगार सृजन प्रभाव का विश्लेषण करता है, विशेष रूप से 2025-2030 के अनुमानित GDP योगदान के संदर्भ में, और चुनौतियों पर प्रकाश डालता है।



## अनुसंधान पद्धति (Research Methodology)

यह अध्ययन वर्णनात्मक और विश्लेषणात्मक है, जो पूरी तरह द्वितीयक डेटा पर आधारित है। डेटा स्रोत निम्न हैं:

आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 (भारत सरकार) NITI Aayog की रिपोर्ट "India's Booming Gig and Platform Economy" (2022)

विभिन्न समाचार स्रोत और रिपोर्ट्स (Forbes India, Down to Earth, PIB आदि) सरकारी प्रकाशन और आंकड़े (RBI, PLFS आदि से संदर्भित)

डेटा संग्रह: ऑनलाइन उपलब्ध रिपोर्ट्स और आधिकारिक दस्तावेजों से। विश्लेषण: प्रवृत्ति विश्लेषण (trend analysis), प्रतिशत वृद्धि गणना, और तुलनात्मक अध्ययन। कोई प्राथमिक सर्वेक्षण नहीं किया गया, क्योंकि उद्देश्य वर्तमान आंकड़ों पर आधारित अनुमानित प्रभाव का मूल्यांकन है।

## मुख्य निष्कर्ष और विश्लेषण (Main Findings and Analysis)

### 1. रोजगार सृजन में वृद्धि-

- FY 2021: 77 लाख गिग वर्कर्स
- FY 2025: 1.2 करोड़ (55% वृद्धि)
- 2029-30 अनुमान: 23.5 मिलियन (NITI Aayog), जिसमें गैर-कृषि गिग कार्यबल 6.7%

यह वृद्धि डिजिटल प्लेटफॉर्म (डिलीवरी, राइड-शेयरिंग, फ्रीलांसिंग) से संचालित है। गिग इकोनॉमी ने अनौपचारिक रोजगार को प्लेटफॉर्म-आधारित रूप दिया है, जिससे युवाओं और ग्रामीण क्षेत्रों में अवसर बढ़े हैं।

### 2. GDP योगदान का अनुमान-

आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार, 2029-30 तक गिग इकोनॉमी ₹2.35 लाख करोड़ GDP में योगदान देगी। यह योगदान मुख्य रूप से लॉजिस्टिक्स, फूड डिलीवरी, ई-कॉमर्स से आएगा। NITI Aayog के



अनुसार, गिग इकोनॉमी 1.25% GDP तक पहुँच सकती है। यह अनुमान स्मार्टफोन और डिजिटल भुगतान की वृद्धि पर आधारित है।

### 3. चुनौतियाँ-

आय अस्थिरता: 40% गिग वर्कर्स की मासिक आय ₹15,000 से कम है।

सामाजिक सुरक्षा की कमी: पेंशन, स्वास्थ्य बीमा, दुर्घटना कवरेज नहीं।

एल्गोरिदमिक प्रबंधन: प्लेटफॉर्म द्वारा कार्य आवंटन में पारदर्शिता की कमी।

कौशल विकास: AI/ML से नौकरी छिनने का खतरा, स्किलिंग की आवश्यकता।

### निष्कर्ष (Conclusion)

गिग इकोनॉमी भारत में रोजगार सृजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई है, जो 2025-2030 के बीच लाखों नौकरियाँ पैदा करेगी और ₹2.35 लाख करोड़ GDP योगदान देगी। यह लचीलेपन और डिजिटल समावेशन प्रदान करती है, लेकिन आय अस्थिरता, सामाजिक सुरक्षा की कमी और श्रमिक अधिकारों की चुनौतियाँ बनी हुई हैं। नीतिगत स्तर पर, सामाजिक सुरक्षा कोड 2020 का प्रभावी कार्यान्वयन, न्यूनतम प्रति-टास्क आय, एल्गोरिदम पारदर्शिता और स्किल डेवलपमेंट आवश्यक है। गिग कार्य को "चॉइस" बनाना चाहिए, न कि "जरूरत"। भविष्य में गिग इकोनॉमी भारत की आर्थिक वृद्धि का मजबूत स्तंभ बन सकती है, यदि श्रमिक-केंद्रित सुधार किए जाएँ।

### संदर्भ (References)

- [1]. आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26, भारत सरकार, जनवरी 2026।
- [2]. NITI Aayog. (2022). India's Booming Gig and Platform Economy: Perspectives and Recommendations on the Future of Work.
- [3]. Forbes India. (2026). Economic Survey warns India's booming gig economy rests on unstable work.



- [4]. Down to Earth. (2026). Economic Survey 2026: India's fast-growing gig economy needs an overhaul.
- [5]. PIB. (2026). Right skilling, entrepreneurial spirit and government initiatives continue to bring down unemployment.
- [6]. विभिन्न अन्य स्रोत: The Hindu, Economic Times, Moneycontrol आदि (2026)।

